आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
सोमवार 27.01.2025 समय 1830

मुख्य समाचार :–

- उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता लागू। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यू.सी.सी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में यूसीसी को लागू करने के लिए नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया। कहा– यह प्रदेश ही नहीं, देश के लिए भी ऐतिहासिक दिन।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे।
- महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आज ''मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना'' की 3 करोड 35 लाख से अधिक की धनराशि, लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की।

<u>यूसीसी लागू</u>

उत्तराखंड में आज समान नागरिक संहिता– यूसीसी लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ''मुख्यमंत्री आवास'' में आयोजित कार्यक्रम में यूसीसी को लागू करने के लिए नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया। इसी के साथ उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया, जहां यह कानून प्रभावी हो गया है। इसके बाद से विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन से अलग होना, विरासत आदि के ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। यूसीसी से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे।

वहीं, इस मौके पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि यूसीसी से समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे सभी वर्ग के लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों को नियमों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि अधिनियम के क्रियान्वयन के दौरान कोई भी समस्या आने पर उसका त्वरित निस्तारण किया जाएगा।

<u>यूसीसी नियम</u>

यूसीसी के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। यूसीसी नियम के तहत पूजा–पद्धति और परंपराओं में कोई बदलाव नहीं किया गया। कोई भी शख्स बहुविवाह नहीं कर पाएगा। सभी के लिए तलाक का कानून एक जैसा होगा। लिव–इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना भी जोड़ों के लिए

अनिवार्य होगा। इस दौरान पैदा होने वाले बच्चे को भी शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर की हिस्सेदारी होगी। यूसीसी में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके लिए कट ऑफ डेट 27 मार्च 2010 रखी गई है। यानी इस दिन से हुए सभी विवाह पंजीकृत कराने होंगे। विवाह का पंजीकरण छह माह के भीतर करना होगा। संहिता लागू होने के बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण विवाह तिथि से 60 दिन के भीतर कराना होगा। यूसीसी के नियम–कानून से अनुसूचित जनजाति को बाहर रखा गया है।

पुलिस ब्रीफिंग

प्रदेश में कल से 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरूआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी देहरादून से इन खेलों का उद्‌घाटन करेंगे। श्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा में नियुक्त किये गये सभी पुलिस बल की आज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम देहरादून में ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग में पुलिस के उच्चाधिकारियों ने बताया कि वीवीआईपी भ्रमण के दौरान कार्यक्रम स्थल और उसके आस–पास दो किलोमीटर के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। साथ ही कार्यक्रम स्थल में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने साथ बैग, पानी की बोतल, खाद्य सामग्री, ज्वलनशील वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। कार्यक्रम स्थल पर केवल अधिकृत व्यक्तियों और उनके वाहनों को ही विधिवत चेकिंग के बाद ही जाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं, राष्ट्रीय खेलों के लिए प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

वात्सल्य योजना

महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आज देहरादून में ''मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना'' की धनराशि, लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की। इस मद में 3 करोड 35 लाख से अधिक रुपए की धनराशि लाभार्थियों को भेजी गयी। श्रीमती आर्या ने बताया कि माह नवम्बर के लिए कुल 5 हजार 603 बच्चों और माह दिसम्बर के लिए कुल 5 हजार 581 बच्चों के खातों में धनराशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में आच्छादित बच्चों को 3 हज़ार रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता, 21 वर्ष की आयु होने तक दी जाती है। योजना के तहत प्रदेश भर में कुल 6 हजार 544 बच्चे चिन्हित किए गए हैं।

उत्तराखंड पुलिस प्रयागराज

प्रदेश के 20 पुलिस अधिकारी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की विभिन्न व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बताया कि वर्ष 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होना है। इस आयोजन से पहले अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है, जो प्रयागराज महाकुंभ में कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन सहित अन्य चुनौतियों का मौके पर अध्ययन करेंगे।

वनाग्नि कार्यशाला

नैनीताल जिले के हल्द्वानी में वनाग्नि प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वनाग्नि को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। हल्द्वानी के प्रभागीय वनाधिकारी कुंदन कुमार ने जंगलों में लगने वाली आग की रोकथाम के लिए स्थानीय लोगों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उनकी सहभागिता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा विकसित किए फॉरेस्ट फायर मोबाइल एप से आम लोगों को भी जोड़ा जा रहा है।

बैठक चमोली

चमोली जिले में आगामी चारधाम यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने को लेकर आज जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पिछले यात्रा अनुभवों और मौजूदा व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई और यात्रा व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए सभी के सुझाव भी लिए गए। जिलाधिकारी ने बदरीनाथ यात्रा मार्ग पर कमेड़ा से लेकर बदरीनाथ तक सड़क किनारे सभी अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने नंदप्रयाग–कोठियासैंण बाइपास चौड़ीकरण करने और नगर पालिका को कोठियासैंण में खाली स्थान पर पार्किंग निर्माण कराने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बदरीनाथ धाम सहित सभी यात्रा पड़ावों और यात्रा रूट पर पेयजल, विद्युत, शौचालय और पार्किंग की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

केंद्रीय बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली फरवरी को वित्त वर्ष 2025–26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। आगामी बजट में घरेलू तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं और राजकोषीय रणनीतियों की झलक देखने को मिलेगी। बजट में मजबूत बुनियादी ढांचे और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर जोर देते हुए आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और राजकोषीय नियंत्रण पर ध्यान दिए जाने की उम्मीद है।